शिलांग, मेघालय में आयोजित होने वाले 20वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन-III सम्मेलन के दौरान माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

श्री कॉनराड के. संगमा, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री:

श्री हरिवंश नारायण सिंह, माननीय उपसभापति, राज्य सभा:

श्री पासंग डी. सोना, माननीय अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा और अध्यक्ष, सीपीए भारत क्षेत्र जोन III:

श्री थॉमस ए. संगमा, माननीय अध्यक्ष, मेघालय विधान सभा:

विधान सभाओं के माननीय सदस्य;

प्रतिनिधिगण और देवियो एवं सज्जनो:

सीपीए इंडिया क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में, मैं सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें मिले स्नेह और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए हम मेजबान सीपीए शाखा के आभारी हैं। यह आयोजन इसलिए खास है क्योंकि यह हमारे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के विधायकों को एक साथ लाता है।

अपनी भव्यता, प्राकृतिक सुंदरता और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाले मेघालय को यहाँ के मेहनती और मैत्रीपूर्ण लोग और ज्यादा जीवंत एवं खास बनाते हैं।

यह भूमि मुझे लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और अत्यंत लोकप्रिय स्वर्गीय श्री पी.ए. संगमा जी की याद दिलाती है। अपने असाधारण चरित्र, प्रतिबद्धता और संकल्पशक्ति के बल पर उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी बेहतरीन कार्य और समाज सेवा करके महान उपलब्धि हासिल की। मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ।

सबसे पहले, मैं इस क्षेत्रीय सम्मेलन को क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और चिंताओं पर विचार-विमर्श के लिए एक उपयोगी मंच बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, सीपीए इंडिया रीजन जोन-III के अध्यक्ष, श्री पसांग डी. सोना जी का आभारी हूं।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सीपीए इंडिया क्षेत्र का जोन-III सभी चार जोनों में सबसे अधिक सक्रिय है। अब तक आयोजित हुए 20 वार्षिक सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मैंने ध्यान दिया है कि इस क्षेत्र की विधान सभाओं की एक विशेषता है कि यहाँ की सभाओं की बैठक में बिना व्यवधान के सार्थक और गंभीर चर्चाएं होती हैं। स्वाभाविक है कि इससे संवाद का सार्थक निष्कर्ष भी निकलता है जो इस क्षेत्र और देश के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। निश्चय ही यह अन्य क्षेत्र के लिए प्रेरणा है।

मुझे खुशी है कि सीपीए जोन III ने बहुत ही उपयुक्त विषयों को चुना है। 'प्राकृतिक आपदाएँ और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ'; और वर्तमान सम्मेलन के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श के विषयों के रूप में 'उत्तर पूर्व क्षेत्र को मुख्य भूमि भारत के बराबर लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी'। ये दोनों विषय बहुत ही प्रासांगिक और समसामयिक हैं।

बदलते जलवायु परिवर्तन के इस युग में हमें अपनी प्रकृति के प्रति अधिक सजग होना होगा। मुझे याद है कि पिछले सम्मेलन में, उत्तर पूर्व के सामने आने वाली असंख्य चुनौतियों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। ये चुनौतियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों की आर्थिक क्षमता के समुचित उपयोग में बाधक हैं जिससे यह क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण मापदंडों के मामले में भारत के कई राज्यों से पिछड़ रहा है।

भारत अपनी अनूठी भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण बड़ी संख्या में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति अलग-अलग स्तर पर संवेदनशील रहा

है। इस वर्ष भी इस क्षेत्र में आपदाओं के कारण जान-माल की भारी हानि हुई है और फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट हैं, और यहाँ होने वाली किसी पारिस्थितिक गड़बड़ी की घटनाओं के पूरे भारत में पर्यावरणीय स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन की कहीं बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे नीतियाँ तैयार हों जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को होने वाली अपूरणीय या अधिक क्षति को रोका जा सके।

दूसरा, लोग प्राकृतिक आपदाओं के खतरों के बारे में जागरूक हों, विपरीत परिस्थितियों में उनसे निपटने के लिए अपने स्तर पर भी तैयार हों, ऐसी व्यवस्था हो।

इसके अलावा आपदा प्रबंधन के स्तर पर, हमें हमारे प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय क्षमताओं और पहल के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, आपदा से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना, और आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व आदि आवश्यक कदम हैं।

जहां तक 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र को मुख्य भूमि भारत के बराबर लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी' की बात है तो मैं समझता हूँ कि उत्तर पूर्व में मुख्य भूमि भारत के बराबर आने की आर्थिक क्षमता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है - बुनियादी ढांचे का विकास ।

पीएम गति शक्ति कार्यक्रम भूमि (सड़क और रेल), वायु और जल क्षेत्र में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों को पुनः बहाल करने के मामले में फायदेमंद साबित हो रहा है।

क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इस योजना के तहत लगभग सात प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा के लिए नागालैंड एक्सप्रेस हाईवे का विकास कार्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पांच राज्यों इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक और शिलांग की शेष राजधानी को जोड़ने के लिए कुल 310 किलोमीटर की नई लाइन परियोजनाएं इस दिशा में एक अहम कदम है।

पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में ऑपेरशनल हवाई अड्डे की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

इसके अलावा, क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र, अंतर्देशीय जलमार्ग, वन/वन्यजीव अभयारण्य, औद्योगिक पार्क आदि में कई परियोजनाएं चल रही हैं।

आज भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जितने बड़े स्तर पर कार्य चल रहे हैं, वह उनके उस कथन को सही सिद्ध कर रहा है जब उन्होंने कहा था, "उत्तर-पूर्व को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाना मेरा दृढ़ विश्वास है।"

आज यहाँ न केवल आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है बल्कि इस क्षेत्र को एशिया और भारत के एक्ट ईस्ट में क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी का 'फोकल प्वाइंट' बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आयाम के स्तर पर भी प्रयास हो रहा है।

मैं समझता हूँ कि भारत की लुक-ईस्ट नीति और नवीनीकृत एक्ट ईस्ट नीति के साथ-साथ पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ विभिन्न

स्तरों पर देश की अधिक भागीदारी से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय एकजुटता बढ़ेगी।

समग्र रूप से देखें तो यह क्षेत्र अब एक व्यापक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट दिखाती है कि सिक्किम और मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से तेजी से उभरे हैं।

विकास के मोर्चे पर, 2019-20 सीएसओ डेटा से पता चलता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में से कुछ ने राष्ट्रीय विकास के आंकड़े को पार कर लिया है।

मिजोरम ने 13 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की और यह भारत का अग्रणी राज्य है। आज़ादी के बाद भारत के आर्थिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

इसके अलावा, पिछले छह वर्षों में इस क्षेत्र में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इससे यह उम्मीद बन गई है कि शीघ्र ही उत्तर पूर्व क्षेत्र कृषि व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

आज, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को न केवल एशिया के सबसे जातीय और भाषाई रूप से विविध क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है, बल्कि इसे अवसरों की भूमि के रूप में भी देखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में अपार संभावनाओं और प्रचुरता के साथ, यह क्षेत्र तेजी से स्थायी पर्यटन, औषधीय पौधों और जीवंत कला और हस्तशिल्प क्षेत्र के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

हमें यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विकास की इस क्रमिक और सतत प्रक्रिया में हम मानवीय मूल्यों और नैतिकता के मार्ग से न भटकें। अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, वह एक मानवीयता के तौर पर, एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर हमारे लिए अत्यंत कष्टदायी है। किसी के भी साथ हमारा व्यवहार उसको

किसी भी तरह की पीड़ा पहुंचाने वाला न हो, उसकी मान-मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला न हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए।

एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। 'सबका साथ, सबका विकास' की हमारी मूल अवधारणा यही तो है।

अंत में, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को लगातार बढ़ावा देने और इस 20वें सीपीए क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए सीपीए भारत क्षेत्र जोन III की प्रशंसा करता हूं।

मैं इस सम्मेलन की मेजबानी की जिम्मेदारी निभाने और उत्कृष्ट व्यवस्था करने के लिए मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री और मेघालय विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करता हूं।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के दौरान क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के सभी विधायक परस्पर सार्थक और रचनात्मक विचार-विमर्श करेंगे और इस तरह के नियमित सम्मेलन देश के तेज विकास के लिए विकासात्मक रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेंगे, जिससे क्षेत्र और जन सामान्य की प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।